



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2004/भाद्र 19, 1926

No. 206]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2004/BHADRA 19, 1926

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(अनुसूचित जाति विकास प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2004

सं. 17015/18/2003-एससीडी-VI.—जबकि सफाई कर्मचारियों और विशेषकर स्कैवेंजर्स की वैकल्पिक उपजीविका के लिए विकास संबंधी आवश्यकताएं और उनका पुनर्वास भारत सरकार के विचाराधीन रहा है।

2. और जबकि सरकार ने स्कीमों के आमेदन के पश्चात् 31 दिसम्बर, 2007 तक सिर पर मैला ढोने की प्रथा (स्कैवेंजिंग) को पूर्णतः समाप्त करने और उनके पुनर्वास में तीव्रता लाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना आरम्भ की है और उसका यह सुविचारित मत है कि लक्ष्य समूह के हित में यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को जारी रखा जाए क्योंकि आयोग को आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक पुनर्वास के कार्य की निगरानी करनी है।

3. अतः अब भारत सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को 1-9-2004 से 31-12-2007 तक जारी रखने का संकल्प किया है जिसकी संरचना इस प्रकार है :—

- (i) इस राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) होंगे;
- (ii) अध्यक्ष राज्य मंत्री के रैंक में तथा 4 अन्य सदस्य भारत सरकार के सचिव के रैंक में होंगे;
- (iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सचिवालय में विद्यमान पदों को 31-12-2007 तक जारी रखना; और
- (iv) विद्यमान कार्यालय आवास को बनाए रखना।

4. आयोग के विचारणीय विषय हैं :

- (क) सफाई कर्मचारियों के लिए स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता समाप्त करने के लिए कार्य योजना के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों की केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना।
- (ख) सफाई कर्मचारियों और विशेषकर स्कैवेंजर्स के सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों एवं स्कीमों के क्रियान्वयन का अध्ययन व मूल्यांकन करना।

(ग) विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना और निम्नलिखित को कार्यान्वित न किए जाने से संबंधित विषयों पर अपनी ओर से ध्यान देना :

- (i) सफाई कर्मचारियों के किसी समूह की बाबत कार्यक्रम या स्कीमें;
- (ii) सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए विनिश्चय, मार्गदर्शन या अनुदेश;
- (iii) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उपाय;
- (iv) सफाई कर्मचारियों को लागू किसी विधि के उपबंध; और ऐसे विषयों को संबंधित प्राधिकारियों अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकारों के साथ उठाना।

(घ) 2007 तक सिर पर मैला ढोने की प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करना।

(ङ) सफाई कर्मचारियों को जिन कठिनाइयों या निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी विषय पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को रिपोर्ट देना।

(च) कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए जाए।

5. आयोग, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी संगठन से ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकेगा जिसे वह अपने प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

6. आयोग अपनी स्वयं की क्रियाप्रणाली अपनाएगा और भारत के किसी भी भाग में जब भी आवश्यक समझे, जा सकेगा।

7. आयोग प्रत्येक वित्त वर्ष की अपनी वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित समय और प्ररूप में तैयार करेगा जिसमें पूर्व वित्त वर्ष के इसके कार्यकलापों का पूरा ब्यौरा होगा और इसकी प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

पी. नारायण मूर्ति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Scheduled Castes Development Division)

### RESOLUTION

New Delhi, the 9th September, 2004

**No. 17015/18/2003-SCD-VI.**—Whereas the Government of India has been seized of the developmental needs and rehabilitation of the Safai Karamcharis and Scavengers in particular, in alternate occupations.

2. And whereas the Government has launched a National Action Plan for the total eradication of manual scavenging after amalgamation of schemes and speeding up the rehabilitation of scavengers by 31-12-2007; the Government is of the considered view that the continuation of the National Commission for Safai Karamcharis is necessary in the interest of the target group as the Commission is required to oversee the economic, social and educational rehabilitation.
3. Now, therefore, the Government of India has resolved to continue the National Commission for Safai Karamcharis for a period from 1-9-2004 to 31-12-2007 with the following Constitution :—
  - (i) a Chairperson and four other Members (including one lady Member).
  - (ii) the Chairperson shall be in the rank of Minister of State and the four other Members shall be in the rank of the Secretary to the Government of India.
  - (iii) the continuation of the existing posts in the Secretariat of National Commission for Safai Karamcharis till the 31st December, 2007.
  - (iv) continuation of the existing office accommodation.
4. The terms of reference of the Commission are given below :
  - (a) Recommend to the Central Government a specific programme of action towards elimination of inequalities in a status, facilities and opportunities for Safai Karamcharis.

- (b) Study and evaluate the implementation of the programmes and schemes relating to the social and economic rehabilitation of Safai Karamcharis and Scavengers particular.
  - (c) Investigate specific grievances and to take *suo-motu* notice of matters relating to non-implementation of :
    - (i) programmes or schemes in respect of any group of Safai Karamcharis;
    - (ii) decisions, guidelines or instructions aimed at mitigating the hardship of Safai Karamcharis;
    - (iii) the measures for social and economic upliftment of Safai Karamcharis;
    - (iv) the provisions of any law in its application to Safai Karamcharis; and take up such matters with concerned authorities or with the Central or State Government;
  - (d) Oversee the implementation of the National Action Plan for total eradication of manual scavenging by 2007.
  - (e) Make reports to the Central and State Governments on any matter concerning Safai Karamcharis, taking into account any difficulties disabilities being encountered by Safai Karamcharis;
  - (f) Any other matter, which may be referred to it by the Central Government.
5. The Commission may obtain such information as considered necessary or expedient for its purpose from the Central Government or any State Government or any authority, organization.
6. The Commission will adopt its own procedure of working and may visit any part of India as and when considered necessary.
7. The Commission shall prepare in such form and at such time for each financial year as may be prescribed its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Central Government.

P. N. MURTHY, Jt. Secy.